



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 531]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 14, 2009/भाद्र 23, 1931

No. 531]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 14, 2009/BHADRA 23, 1931

वित्त मंत्रालय

( राजस्व विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2009

सं. 104/2009-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 674(अ)—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, एतद्वारा, ऐसे पूंजीगत माल, जो विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 3.16 में विनिर्दिष्ट हैं तथा जब उनको स्टेटस होल्डर्स इंसेन्टिव स्कीम के अंतर्गत जारी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (एतश्मिन पश्चात जिसे 'स्क्रिप' से संदर्भित किया गया है), के प्रति भारत में आयात किया गया हो, को

(क) सीमा शुल्क तटकर अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत उस पर लगाये जा सकने वाले सम्पूर्ण शुल्क से, तथा

(ख) उक्त सीमा शुल्क तटकर अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अंतर्गत उस पर लगाये जा सकने वाले सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क से निम्नलिखित शर्तों के अधीन छूट प्रदान करती है, यथा:

(i) यह कि उल्लिखित स्क्रिप स्टेटस होल्डर को क्षेत्रों के उत्पादों के निर्यात के बदले यथा चमड़ा (तैयार चमड़े को छोड़कर), कपड़ा और जूट, हैंडिक्राफ्ट, इंजीनियरिंग (लोहा एवं इस्पात को छोड़कर, नान फेरस मेटल, प्राथमिक या इंटरमिडियेट रूप में ओटोमोबाइल एवं दुपहिया, न्यूक्लीयर रियेक्टर और इसके भाग, जहाज, नावें एवं बहने वाली संरचनाएं); प्लास्टिक और मूल रसायन (फार्मा उत्पाद को छोड़कर) जारी की गई है।

बशर्ते कि उपरोक्त उल्लिखित क्षेत्रों के उत्पाद का निर्यात वर्ष 2009-10 और 2010-11 किया गया हो, को ही इस योजना के अंतर्गत अर्हक माना जाएगा।

बशर्ते कि इस अधिसूचना के साथ दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट निर्यात को इस योजना के अंतर्गत गणना में नहीं माना जाएगा।

(ii) यह कि इस छूट के उल्लिखित स्क्रिप उचित सीमा शुल्क अधिकारी के समक्ष वस्तुओं पर उदग्रहणीय शुल्कों पर नामे की निकासी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

(iii) यह कि उल्लिखित स्क्रिप अहस्तांतरणीय होगी और दशा (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों से संबंधित पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए प्रयुक्त होगी

बशर्ते कि प्रक्रिया की हैण्ड बुक के खण्ड 1 में परिशिष्ट 37ख में विनिर्दिष्ट पूंजीगत माल हेतु आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iv) यह कि विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत आयात किए गए पूंजीगत माल वास्तविक प्रयोगकर्ता की शर्त के अधीन और उक्त पूंजीगत माल के क्लिएरेंस के वक्त आयातकर्ता, उपायुक्त सीमा शुल्क या सहायता आयुक्त, सीमा शुल्क जैसा भी स्थिति हो, के समक्ष इस आशय की अंडरटेकिंग देगा कि उक्त शर्तों को पूरा न हो पाने की स्थिति में वह लगाए जा सकने वाले शुल्क के बराबर की राशि को मार्गे जाने पर भुगतान कर देगा तथा उक्त माल की निकासी की तारीख से उक्त छूट पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देना होगा।

(V) यह कि आयात आयात और निर्यात समुद्री बंदरगाह-बेदी (रोजी-जामनगर सहित), चेन्नई, कोचीन, दहेज, धरमतर, हल्दिया (कोलकता बंदरगाह का हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स), काकीनाडा, कांडला, कोलकता, कृष्णापटनम, मागडाल्ला, मंगलौर, मारमगोवा, मुलद्वारका, मुम्बई, मुन्धरा, नागापट्टिनम, न्हावा शेवा, ओखा, पारादीप, पिपाव, पोरबंदर, सिक्का, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम तथा वदिनार के माध्यम से से अथवा अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोचीन, कोयम्बतूर, डबोलिम(गोवा), दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ (अमौसी), मुम्बई, नागपुर, राजासांसी (अमृतसर), श्रीनगर, त्रिवेन्द्रम तथा वाराणसी स्थित किसी विमानपत्तन के जरिए अथवा आगरा, अहमदाबाद, अनापार्थी (आंध्र प्रदेश), बाबरपुर, बंगलौर, भदोही, भटिन्डा, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, भुसावल, छेहाड़ता (अमृतसर), कोयम्बतूर, दादरी, डाप्पर (डैरा बस्सी), दौलताबाद (वंजारवाड़ी तथा मालीवाड़ा), दिल्ली, डिगही (पुणे), दुर्गापुर

(निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क), फरीदाबाद, गरही हरसारू, गौहाटी, गुंटूर, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, जमशेदपुर, जोधपुर, कानपुर, करूर, कोटा, कुंडली, लोनी (जिला गाजियाबाद), लुधियाना, मदुरै, मलांपुर, मंडीदीप (जिला रायसेन), मिराज, मुरादाबाद, नागपुर, नासिक, पिम्परी (पुणे), पीतमपुर (इंदौर), पांडिचेरी, रायपुर, रेवाड़ी, रूद्रपुर (नैनीताल), सलेम, सिंगनालूर, सूरत, सूरजपुर, तिरुपुर, तूतीकोरिन, उदयपुर, वडोदरा, वाराणसी, वालुज (औरंगाबाद) स्थित किसी इनलैंड कंटेनर डिपो के माध्यम से अथवा अगरतल्ला, अमृतसर रेल कार्गो, अटारी रोड, चांगराबांथा, डावकी, घोजाडंगा, हिल्ली, जोगबानी, महादीपुर, नोपालगंज रोड, नौतनवा (सौनोली), पेटरापोल, राणाघाट, रक्सौल, सिंघाबाद तथा सुतारखंडी भू-सीमा शुल्क स्टेशन के जरिए अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन के माध्यम से किए जाते हैं।

यह प्रावधान है कि सीमा शुल्क आयुक्त अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विशेष आदेश द्वारा अथवा सार्वजनिक नोटिस द्वारा और उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन किसी अन्य समुद्री बंदरगाह, विमानपत्तन, इनलैंड कंटेनर डिपो अथवा भू सीमा शुल्क स्टेशन के माध्यम से आयात और निर्यात की अनुमति प्रदान कर सकते हैं।

(vi) यह कि आयातकर्ता सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उदग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क से छूट का दावा नहीं करता है तो उसे इस उल्लिखित अतिरिक्त सीमा शुल्क की गणना के उद्देश्य से उस छूट का लाभ नहीं लिया हुआ माना जाएगा।

(vii) आयातकर्ता उक्त स्क्रिप में डेबिट की गई राशि के एवज में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत लगाये जा सकने वाले अतिरिक्त शुल्क के ड्रा बैंक या सेनवेट क्रेडिट के लिए हकदार होगा।

### तालिका

| क्रम संख्या | विवरण   |
|-------------|---|
| 1           | ईओयू/ईएचटीपी/बीटीपी जो कि प्रत्यक्ष कर का लाभ/छूट ले रहे हैं। |

|   |  |
|---|--|
| 2 | विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.35 के अंतर्गत आने वाले आयातित माल का निर्यात  |
| 3 | ट्रांसशिपमेंट के माध्यम से किये जाने वाले निर्यात, जिसका अर्थ यह है कि निर्यात का प्रारंभ किसी तीसरे देश से हुआ है लेकिन उसकी ट्रांसशिपिंग भारत के रास्ते हो रही हो। |
| 4 | मानद निर्यात   |
| 5 | एसईजेड एककों द्वारा किया जाने वाला निर्यात या डीटीए एककों के माध्यम से निर्यातित एसईजेड उत्पाद; और   |
| 6 | ऐसे मद जो आईटीसी(एचएस) में निर्यात नीति के अनुसूची-2 के अंतर्गत निर्यात के लिए प्रतिबंधित या निषिद्ध है।   |
| 7 | स्टेटस होल्डर द्वारा किसी विशिष्ट वर्ष में किया गया निर्यात यदि उस वर्ष में कपड़ा मंत्रालय द्वारा तकनीकी उन्नयन कोष योजना (टीयूएफएस के अंतर्गत लाभ उठाए गए थे)।      |
| 8 | जीरो ड्यूटी ईपीसीजी योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2010 से किए गए निर्यात  |

स्पष्टीकरण :- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, -

- (i) 'पूंजीगत माल' का अर्थ किसी प्लांट, उपकरण या साजोसामान जो विनिर्माण या उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं हेतु आवश्यक है, या सेवाएं देने हेतु आवश्यक है, जिसमें वस्तु बदलना, आधुनिकीकरण, तकनीकी उन्नयन या विस्तार शामिल है। इसमें पैकिंग मशीनरी और उपकरण, इनिशियल लाइनिंग के लिए रिफेक्टरी, रेफ्रिजिरेशन उपकरण, ऊर्जा उत्पादक सेट, मशीन टूल, इनिशियल चार्ज के लिए उत्प्रेरक, जांच के लिए उत्प्रेरक एवं औजार, शोध एवं विकास, गुणवत्ता एवं प्रदूषण नियंत्रण शामिल है। पूंजीगत माल का विनिर्माण, खनन, कृषि, एक्वाकल्चर, पशुपालन, फ्लोरीकल्चर, हार्टिकल्चर, विसिकल्चर, मुर्गीपालन, रेशम कीट पालन एवं विटिकल्चर में प्रयोग हो सकता है, साथ ही सेवा क्षेत्र में प्रयोग हो सकता है।

- (ii) 'विदेश व्यापार नीति' का अर्थ है विदेश व्यापार नीति 2009-2014 है जिसे भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 1/2009-2014, दिनांक 27 अगस्त, 2009 समय-समय पर यथा संशोधित से है।

[फा. सं. 605/58/2009-डी बी के]

राजेश कुमार अग्रवाल, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th September, 2009

**No. 104/2009-CUSTOMS**

**G.S.R. 674(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the capital goods when imported into India against a duty credit scrip issued under the Status Holders Incentive Scheme in accordance with paragraph 3.16 of the Foreign Trade Policy (hereinafter referred to as the said scrip),

- (a) from the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), and
- (b) from the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act, 1975,

subject to the following conditions, namely :-

- (i) that the said scrip has been issued by the licensing Authority to a status holder against exports of the products of the sectors, namely, leather (excluding finished leather), Textiles and Jute, Handicrafts, Engineering (excluding Iron and Steel, Non Ferrous Metals in primary or intermediate forms, Auto mobiles & Two wheelers, Nuclear reactors and parts and ships, Boats and Floating structures), plastic and basic chemicals(excluding Pharma Products):

Provided that the exports of the products of the above said sectors, made during 2009-10 and 2010-11 shall only be considered for entitlement under the scheme:

Provided further that, the exports specified in the Table annexed to the notification shall not be considered for computation of entitlement under the scheme;

- (ii) that the said scrip is produced before the proper officer of customs at the time of clearance for debit of the duties leviable on the goods, but for this exemption;
- (iii) that the said scrip shall be non-transferable and shall be used for import of capital goods relating to the sectors specified in condition (i) :

Provided that, the capital goods specified in Appendix 37 B of Hand Book of Procedures Vol.1 shall not be allowed for import;

3353 AI/09-2

- (iv) that the capital goods imported against the said scrip shall be subject to actual user condition and the importer at the time of clearance of the said capital goods, shall furnish an undertaking to this effect to the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, that in case of non compliance of the said condition, he shall pay on demand an amount equal to the duty leviable, but for the exemption contained herein together with interest at the rate of fifteen percent per annum from the date of clearance of the said materials;
- (v) that the imports and exports are undertaken through seaports at Bedi (including Rozi-Jamnagar), Chennai, Cochin, Dahej, Dharamtar, Haldia (Haldia Dock complex of Kolkata port) Kakinada, Kandla, Kolkata, Krishnapatnam, Magdalla, Mangalore, Marmagoa, Muldwarka, Mumbai, Mundhra, Nagapattinam, Nhava Sheva, Okha, Paradeep, Pipavav, Porbander, Sikka, Tuticorin, Visakhapatnam and Vadinar or through any of the airports at Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Chennai, Cochin, Coimbatore, Dabolim (Goa), Delhi, Hyderabad, Indore, Jaipur, Kolkata, Lucknow (Amausi), Mumbai, Nagpur, Rajasansi (Amritsar), Srinagar, Trivandrum and Varanasi or through any of the Inland Container Depots at Agra, Ahmedabad, Anaparthi (Andhra Pradesh), Babarpur, Bangalore, Bhadohi, Bhatinda, Bhilwara, Bhiwadi, Bhusawal, Chheharata (Amritsar), Coimbatore, Dadri, Dappar (Dera Bassi), Daulatabad (Wanjarwadi and Maliwada), Delhi, Dighi (Pune), Durgapur (Export Promotion Industrial Park), Faridabad, Garhi Harsaru, Gauhati, Guntur, Hyderabad, Jaipur, Jalandhar, Jamshedpur, Jodhpur, Kanpur, Karur, Kota, Kundli, Loni (District Ghaziabad), Ludhiana, Madurai, Malanpur, Mandideep (District Raisen), Miraj, Moradabad, Nagpur, Nasik, Pimpri (Pune), Pitampur (Indore), Pondicherry, Raipur, Rewari, Rudrapur (Nainital), Salem, Singanalur, Surat, Surajpur, Tirupur, Tuticorin, Udaipur, Vadodara, Varanasi, Waluj (Aurangabad) or through the Land Customs Station at Agartala, Amritsar Rail Cargo, Attari Road, Changrabandha, Dawki, Ghojadanga, Hilli, Jogbani, Mahadipur, Nepalganj Road, Nautanva (Sonauli), Petrapole, Ranaghat, Raxaul, Singhabad and Sutarkhandi or a Special Economic Zone notified under section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005):

Provided that the Commissioner of Customs may with in the jurisdiction, by special order, or by a Public Notice, and subject to such conditions as may be specified by him, permits import and export from any other seaport/airport/inland container depot or through any land customs station;

- (vi) that where the importer does not claim exemption from the additional duty of customs leviable under section 3 of the said Customs Tariff Act, he shall be deemed not to have availed the exemption from the said duty for the purpose of calculation of the said additional duty of customs;
- (vii) that the importer shall be entitled to avail of the drawback or CENVAT credit of additional duty leviable under section 3 of the said Customs Tariff Act against the amount debited in the said scrip.

TABLE

| Sl.No. | Description  |
|--------|--|
| 1      | EOUs / EHTPs / BTPs who are availing direct tax benefits or exemption  |
| 2      | Export of imported goods covered under para 2.35 of the FTP .  |
| 3      | Exports through transshipment, meaning thereby that exports originating in third country but transhipped through India   |
| 4      | Deemed exports   |
| 5      | Exports made by Special Economic Zone units or Special Economic Zone products exported through Domestic Tariff Area units  |
| 6      | Export of items, which are restricted or prohibited for export under Schedule-2 of Export Policy in ITC (HS).  |
| 7      | The exports made by the Status Holders during a particular year, if benefits are availed under Technology Upgradation Fund scheme (TUFS) of Ministry of Textiles in that year. |
| 8      | The exports made under the Zero duty EPCG scheme w.e.f 1 <sup>st</sup> April, 2010.  |

Explanation, - For the purposes of this notification,-

- (i) "Capital goods" means any plant, machinery, equipment or accessories required for manufacture or production, either directly or indirectly, of goods or for rendering services, including those required for replacement, modernization, technological up gradation or expansion. It also includes packaging machinery and equipment, refractories for initial lining, refrigeration equipment, power generating sets, machine tools, catalysts for initial charge, equipment and instruments for testing, research and development, quality and pollution control. Capital goods may be for use in manufacturing, mining, agriculture, aquaculture, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture, poultry, sericulture and viticulture as well as for use in services sector.
- (ii) "Foreign Trade Policy" means the Foreign Trade Policy 2009-2014, published by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry vide notification No.01/2009-14, dated the 27<sup>th</sup> August, 2009, as amended from time to time.
- (iii) "Licensing Authority " means the Director General of Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation ) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorised by him to grant a licence under the said Act.

[F. No. 605/58/2009-DBK]  
RAJESH KUMAR AGARWAL, Under Secy.